

~~A~~ ~~1~~

08/4/24


पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष हाजिर। वकील उभय पक्ष बरस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 22.4.24 को पेश हो।

~~A~~ ~~1~~

22/4/24

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष बरस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बरस में बताया कि वादग्रस्त आराजियात मौरुसी जायदाद है जो प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी का उक्त आराजियात में 1/3 हिस्सा मिले है। अप्रार्थीगण द्वारा जिन रूपों के खर्च होने की बात कही है और जो हिसाब किताब बताया है वो सही नहीं है तथा यह सिविल न्यायालय का मामला है। प्रार्थी पर यदि रुपये उधार थे तो उसको चुकाने का कोई अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है। दादी गया था तथा दादी के नाम की श्रमि अप्रार्थीगण द्वारा बेची गयी। प्रार्थी उस समय नाबालिग था



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
	<p> प्रार्थी की बिना सहमति के अप्रार्थी द्वारा भूमि का बेचान किया गया जो विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी सं. 2 का पुत्र अपना कर्जा चुकाने हेतु भूमि विक्रय करना चाहता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावेंद फरमाया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि जमीन राउलार्द पैट्रूक (मौरूसी) नहीं है, उक्त वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थी सं. 1 की निजी खातेदारी की है। राजस्व रेकॉर्ड में भी अप्रार्थी संख्या-1 रेकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज सादप पेश नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो कि उक्त आराजियात मौरूसी है। प्रार्थी को वाद। प्रार्थना-पत्र लाने का कोई अधिकार ही नहीं है। एक रेकॉर्ड खातेदार ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र लाने का अधिकारी है जबकि प्रार्थी रेकॉर्ड खातेदार नहीं है। दावा केवल निषेधाज्ञा का है 08 RTA का नहीं पेश किया गया है। किसी रेकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने दोनों पुत्रों की पढाई-लिखाई हेतु पूर्व में भी भूमि का बेचान किया जिसका प्रार्थी द्वारा कभी कोई उजर ऐतराज नहीं किया गया। प्रार्थी ना खातेदार है और ना ही प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का नहीं बनता है। ना ही प्रार्थी को कोई हानि हो रही है। असुविधा को अप्रार्थी को हो रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना- पत्र धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज फरमाया जावे। खब्दन (Rebuttal) बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि जवाब प्रार्थना- पत्र में खरीदशुदा आराजियात संबंधी कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किये जाये हैं। प्रार्थी द्वारा मौरूसी जमाबंदी की नकल पेश कर रखी है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा हटा पावेंद </p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुए।

करवाया जावे। खण्डन (Rebuttal) बहस में वकील
अप्राधीगम ने बताया कि आराजियात मौरूसी है तो
उसको साबित करने का भार प्राधी पर है। प्राधी
द्वारा पेश जमाबंदी नकल से यह सिद्ध नहीं होता
है कि जमीन मौरूसी है अतः प्राधी का प्राधान्य-पत्र
खारिज करमाया जावे। वकील अप्राधीगम ने बहस
के साथ R.R.D 1994 पेज नं० 20 से 22, R.R.T 2003(2)
पेज नं० 1341 से 1345 के दस्तावेज भी पेश किये।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व
उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दस्तावेजों का अवलोकन
किया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन
किया। प्राधी रेकॉर्ड खातेदार नहीं है। प्राधी द्वारा
जमीन के मौरूसी होने काबत भी कोई दस्तावेज
पेश नहीं किया गया। अस्थायी निवेद्याज्ञा के
तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का
संतुलन व अपूरणीय क्षति प्राधी अपने पक्ष में
सिद्ध करा जाने में असमर्थ रहा है। अतः वकील
उभय पक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध
दस्तावेजात के आधार पर प्राधी का प्राधान्य-पत्र
अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी आधिनियम
1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज
किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार ठेकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर है।

निर्णय आज दिनांक 22-04-2024 को
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

A
22-4-24

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

